DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------------- अमर उजाला amarujala.com

नई दिल्ली | बृहस्पतिवार, 16 मार्च 2023

हर घर में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने मंत्रियों व अधिकारियों के साथ बैठक की

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हर घर को साफ और भरपूर पानी उपलब्ध कराने के लिए बुधवार को कैंप कार्यालय पर जल मंत्री सौरभ भारद्वाज, वन मंत्री गोपाल राय, मुख्य सचिव और संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पानी की उपलब्धता बढ़ाने व पानी का संपूर्ण इस्तेमाल करने पर विशेष बल दिया। साथ ही, इस दिशा में चल रहे दिल्ली जल बोर्ड के कामों को निर्धारित समय से पहले पूरा करने के निर्देश दिए।

इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के पास मौजूद पानी के संपूर्ण इस्तेमाल और उसकी बर्बादी रोकने के लिए समयबद्ध काम किया जाए। सभी ट्यूबवेल चालू हों, नए ट्यूबवेल लगाने का कार्य तेजी से किया जाए और खराब ट्यूबवेल 24 घंटे के अंदर ठीक किए जाएं। पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नए एसटीपी का काम जल्द पूरा किया जाए। वहीं, उन्होंने हरियाणा से आने वाले पानी में उपलब्ध अमोनिया को साफ करने का एक सप्ताह में प्लान मांगा है। इसके अलावा उन्होंने मुख्य सचिव को जमीन संबंधित समस्या के निपटारे के लिए डीडीए के साथ सामंजस्य स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जमीन मिलने के छह महीने के अंदर ट्यूबवेल लगा दिए जाएं और जितने भी ट्यूबवेल लग गए हैं, वहां यूजीआर पर पानी की बर्बादी रोकने के लिए वाटर फ्लो मीटर लगाने का काम जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी ट्यूबवेल चालू हालत में होने चाहिए और उससे जितना पानी मिल रहा है, उसकी आपूर्ति की जाए। कोई खराब ट्यूबवेल चार दिनों तक ठीक नहीं होने की स्थिति में संबंधित इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

वजीराबाद में बनेगा अमोनिया रिमूवल प्लांट

मुख्यमंत्री ने कहा कि वजीराबाद में अमोनिया रिमूवल प्लांट लगाया जाएगा। इसका एक सप्ताह के अंदर पूरा प्लान बनाकर प्रस्तुत किया जाए। यहां से वीआईपी एरिया में पानी की आपूर्ति की जाती है। इसे प्राथमिकता से लिया जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा से आने वाले पानी में अगर अमोनिया है तो उसे साफ किया जाए। अमोनिया की वजह से पानी की आपूर्ति रुकनी नहीं चाहिए। वहीं, उन्होंने कोंडली एसटीपी को अपग्रेड करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोंडली एसटीपी से संजय लेक और पार्कों में भी पानी दिया जाए। अगले तीन महीने में जब रिठाला एसटीपी भी तैयार हो जाएगा, तब वहां से भी इरादतनगर और डीडीए की डेड लेक तक पानी लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा भलस्वा समेत अन्य लेक में भी पानी पहुंचाया जाए और वाटर बॉडी को रिचार्ज किया जाए।

मुख्यमंत्री ने दिसंबर तक चंद्रावल संयंत्र तैयार करने के आदेश दिए

अमर उजाला ब्यूरो

निर्माणाधीन चंद्रावल प्लांट

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को चंद्रावल में निर्माणाधीन 105 एमजीडी जल शोधक संयंत्र का दौरा किया। इस दौरान प्रगति निर्धारित समय सीमा के अनुसार नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को दिसंबर तक पूरा करने के लिए एजेंसी से 24 घंटे में विस्तृत योजना सौंपने के आदेश दिए।

उन्होंने कहा कि यह संयंत्र शुरू होने से दिल्ली के 22 लाख लोगों को घर में साफ पानी मिलने लगेगा। चंद्रावल संयंत्र को पूरी तरह से अपग्रेड कर नया बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इसकी क्षमता 105 एमजीडी की हो जाएगी। अभी करीब 90 एमजीडी क्षमता है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे साइट पर तुरंत कर्मचारी व मशीनरी बढ़ाएं और किसी भी तरह की ढिलाई की गुंजाइश न छोड़ें। वे खुद एक इंजीनियर है और समझते है कि प्रोजेक्ट स्थल पर कैसे कार्य किया जाता है। वे ठेकेदार की ओर से किसी भी प्रकार की कमियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मौजूदा व्यवस्था पर असंतोष जताते हुए संयंत्र में अमोनिया ट्रीटमेंट के प्रावधान शामिल करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को ऐसी प्रणाली स्थापित करने के लिए विशेषज्ञों के साथ समन्वय बनाकर काम करने के लिए कहा जो पानी में मौजूद अमोनिया को ट्रीट कर सके।

यमुना डूब क्षेत्र की झुग्गियों को तीन दिन में खाली करें, नहीं तो होंगी ध्वस्त : हाईकोर्ट

झुग्गी नहीं खाली करने वालों को देना होगा 50 हजार रुपये

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना डूब क्षेत्र में रहने वालों को तीन दिन के भीतर अपनी झुग्गियां खाली करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर प्रत्येक झुग्गीवाले को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूबिस) को 50,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को झुग्गियों को गिराने की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति भी दे दी।

अदालत को बताया गया कि उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली एक समिति ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के 9 जनवरी के निर्देशों के मद्देनजर यमुना को साफ करने के निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने बेला एस्टेट, राजघाट में यमुना डूब क्षेत्र में स्थित मूलचंद बस्ती के निवासियों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फ़ैसला सुनाया। साथ ही पुलिस को डीडीए को पूरी मदद देने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने झुग्गीवासियों के वकील से कहा, आप यमुना नदी पर कब्जा कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि इससे कितना नुकसान हो रहा है? ब्यूरो

>> एक लाख से अधिक होंगे प्रभावित : पेज 11

कोई ढिलाई नहीं बरती जाए

अदालत ने डूसिब को एक हलफनामे में कहा कि निवासी पुनर्वास के हकदार नहीं थे, क्योंकि उनकी बस्ती अधिसूचित सूची में नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं या उनके परिवारों के साथ कोई ढिलाई नहीं दिखाई जाएगी। अदालत ने निवासियों की तरफ से दायर अवमानना याचिका को खारिज करते हुए जज ने कहा कि अफसरों को धमकाने के लिए अवमानना कार्यवाही का उपयोग नहीं कर सकते हैं।

हाईकोर्ट के आदेश से एक लाख से अधिक लोग होंगे प्रभावित

नई दिल्ली। हाईकोर्ट के यमुना नदी के बाढ़ वाले क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश के बाद करीब 25 हजार झुग्गियों पर टूटने की तलवार लटक गई है। इन झुग्गियों में एक लाख से अधिक लोग रहते है। तिमारपुर से ओखला के बीच यमुना के दोनों किनारों पर बसी झुग्गियों को हटाना पुलिस प्रशासन और डीडीए को खासी मशक्कत भी करनी पड़ेगी।

करीब 50 झुग्गी बस्तियां हैं यमुना डूब क्षेत्र में

राजधानी में यमुना नदी के दोनों ओर वर्षों से झुग्गी बस्तियां बसी हैं। हालांकि, एक दशक पहले तक कई बार झुग्गियां हटाई गईं मगर अब भी यमुना नदी के क्षेत्र में झुग्गी बस्ती है। इस क्षेत्र में करीब 50 झुग्गी बस्ती बसी हुई है, इन बस्तियों में दो सौ से लेकर छह सौ तक झुग्गियां बनी हुई है और उनमें करीब 25 हजार झुग्गियां बनी है।

सियासी पारा चढ़ने के आसार : हाई कोर्ट के आदेश के तहत यमुना नदी के किनारे से झुग्गी हटाने की कार्रवाई आरंभ होने पर राजधानी में राजनीतिक पारा चढ़ सकता है। क्योंकि डीडीए के साथ-साथ दिल्ली की आप सरकार के अधीन शहरी विकास आश्रय सुधार बोर्ड ने भी झुग्गी हटाने का कार्य करना है। दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोगों के बेघर होने पर सरकार के समक्ष उनके पुनर्वास करने की चुनौती होगी। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAP 16 मार्च • 2023 राष्ट्रीय सहारा -DATED- अमर उजाला

दिल्लीवालों को मिलेगा पर्याप्त शुद्ध पेयजल : केजरीवाल

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवालों को भरोसा दिलाया है कि गर्मी के मौसम में सभी को पर्याप्त पीने का पानी मिलेगा। इसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और वह (मुख्यमंत्री) खुद निगरानी कर रहे हैं। बुधवार को समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पेयजल की बर्बादी रोककर उपलब्धता बढ़ाने एवं किल्लत दूर करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा है कि सभी ट्यूबवेल चालू शुरू किए जाएं और नए ट्यूबवेल का काम भी तेज किया जाए। बैठक में मौजूद मुख्य सचिव को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के साथ बेहतर सामंजस्य बनाने को कहा। हरियाणा से आने वाले पानी को अमोनिया से किस तरह ट्रीट किया जाए, इसके लिए सप्ताहर में प्लान तैयार करने को कहा है। बैठक में मुख्यमंत्री ने लेक को रिचार्ज कर पेयजल की निकासी पर जोर दिया। बैठक के बाद मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि छह महीने के भीतर यमुना के पानी को ट्रीट करने के लिए एसटीपी काम करने

डिटेल प्रोजेक्ट पर काम कर रही सरकार : मुख्यमंत्री

पेयजल की बर्बादी रोककर उपलब्धता बढ़ाएं अधिकारी

डीडीए के साथ सामंजस्य बनाएं मुख्य सचिव

छह माह में यमुना के पानी को ट्रीट करने के लिए शुरू होगा एसटीपी : भारद्वाज

लगेगा। बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, मुख्य सचिव, डूसिब के सीईओ एवं विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने अगली समीक्षा बैठक 25 मार्च को बुलाई है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यूजीआर पर वाटर फ्लो मीटर लगाने का काम जल्द पूरा करने के कहा। जिससे यह पता चल सके। आरओ और फ्लो मीटर लगने से कौन सा ट्यूबवेल चल रहा है और कौन सा बंद है। मुख्यमंत्री ने डीडीए के साथ मुख्य सचिव को सामंजस्य बनाने के साथ ही सौरभ भारद्वाज को अन्य विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लेक में पानी ले जाकर डालते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। लेक बनने के कितने दिनों बाद तक उसमें पानी डालेंगे और कितना पानी निकालेंगे। इस पर एक एसओपी तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने लेक के साथ आरओ प्लांट लगाने का काम 30 सितम्बर तक पूरा करने के निर्देश दिए। सरकार वजीराबाद में अमोनिया रिमूवल प्लांट लगाने जा रही है। सप्ताह भर में पूरा प्लान प्रस्तुत करने को कहा है। केजरीवाल ने एक सप्ताह के भीतर वाटर बॉडीज का दोबारा सर्वे करने के निर्देश दिए। डीडीए के इलाके में करीब 250 वाटर बॉडीज हैं। मुख्यमंत्री ने कोंडली एसटीपी को अपग्रेड करने को कहा है। इस पानी का इस्तेमाल पार्कों की सिंचाई में किया जाएगा। दिल्ली में अभी 1200 वाटर टैंकर है। यह संख्या भी बढ़ाने को कहा।

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के आवंटियों को मिलेंगे तीन विकल्प

नई दिल्ली। मुखर्जी नगर में जर्जर हो चुके अपार्टमेंट में रहने वालों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की तरफ से जल्द राहत मिलेगी। इसके तहत उन्हें तीन विकल्प दिए जा रहे हैं।

मुखर्जी नगर में जर्जर हो चुके अपार्टमेंट का मामला

पुनर्वास के लिहाज से तमाम पहलुओं को देखने के बाद तीनों विकल्प रखे गए हैं। इसके तहत आवंटियों को दूसरी योजना के तहत फ्लैट, किराये पर फ्लैट सहित बायबैक का भी विकल्प दिया जा रहा है। मुखर्जी नगर में आवंटित फ्लैटों की बदहाली और जर्जर हालत को देखते हुए आवंटियों ने इसकी शिकायत एलजी से की थी। इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार मामले की जांच के आदेश दिए थे। तीनों विकल्प के तहत बायबैक, किराये पर फ्लैट के साथ साथ डीडीए के खाली फ्लैटों में शिफ्ट होने का भी प्रावधान रखा जा रहा है। अपार्टमेंट का निर्माण करीब 12-13 साल पहले किया गया था। अपार्टमेंट में 336 एचआईजी और एमआईजी के फ्लैट्स हैं।

निर्माण के बाद अपार्टमेंट के फ्लैटों में दरारें आने और क्षतिग्रस्त होने की शिकायतें होने लगी थीं। सभी आवंटियों के पुनर्वास का काम पूरा होने तक इसे नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। ब्यूरो

साबरमती की तर्ज पर विकसित होगा मिलेनियम पार्क

नई दिल्ली (एसएनबी)। यमुना नदी के मुहानों को ईको फ्रेंडली बनाने के लिए आजकल दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। डीडीए की योजना है कि यमुना के किनारे बने मिलेनियम डिपो को गुजरात की साबरमती नदी के किनारों की तर्ज पर विकसित किया जाए। यमुना नदी के दोनों तरफ चल रहे विकास कार्यों के निरीक्षण के लिए उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष के सुभाषीष पांडा के साथ आईटीओ के पास बने 'असिता ईस्ट' पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उप-राज्यपाल ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह पार्क पर्यावरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

यमुना किनारे बने असिता ईस्ट पार्क पहुंचे उप-राज्यपाल

एलजी ने कहा कि मिलेनियम डिपो को आने वाले समय में पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसे गुजरात की तर्ज पर विकसित करने की योजना है, जिससे लोग यहां आकर प्रकृति का नजारा ले सकें। 'असिता ईस्ट' को जी-20 सम्मेलन के मद्देनजर जल्द से जल्द बेहतर बनाने की कवायद चल रही है। उन्होंने कहा कि असिता पार्क दिल्ली के पर्यावरण और हरियाली की लाइफ लाइन बनेगा। उन्होंने लोगों से भी पर्यावरण के लिए काम करने की अपील की। इस पार्क का नाम असिता रखने के उद्देश्य का जिक्र करते हुए कहा कि यमुना नदी का एक नाम असिता भी है।

डीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि असिता ईस्ट पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए प्राकृतिक उपहार है। उन्होंने नरेला समेत अन्य स्थान पर डीडीए की लंबित परियोजनाओं का जिक्र किया। डीडीए के अधिकारियों का दावा है कि विदेशी मेहमानों को भी काफी पसंद आएगा। इसमें पॉपी, नीलकूपी, एलाइमस, कासमास सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे और फूल खिले दिखे। लाल, पीले, सफेद, गुलाबी रंग के फूलों की सुगंध सभी को लुभा रही थी।

उन्होंने बताया कि जगह-जगह सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं। यह प्वाइंट मेहमानों को भी पसंद आएंगे। यह मेहमानों का ध्यान खींचेगा। यहां चार हजार से अधिक पेड़ लगाए जा रहे हैं। इसमें 800 गोल्डन बांस और तीन खजूर के पेड़ भी शामिल हैं। आईटीओ वैराज के पास पुराने रेलवे पुल से सटी 197 हेक्टेयर भूमि को विकसित करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE
DATED

the pioneer
NEW DELHI | THURSDAY | MARCH 16, 2023

CM assures uninterrupted water supply in Delhi during summer

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

As the city stares at water crisis in the peak summer months, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on Wednesday assured uninterrupted water supply during the summer after a high-level meeting with Water Minister Saurabh Bhardwaj, Forest Minister Gopal Rai, and other stakeholders. During the meeting, a detailed presentation was made by Delhi Jal Board (DJB) and its preparations to ensure ample water supply during summer.

During the meeting, the CM instructed officials to recharge ground water, increase water availability through tube wells, bring uniformity in the quality of water extracted from lakes, and treat the ammonia present in water coming from Haryana.

The CM emphasized the importance of timely utilisation of available water and preventing its wastage. The CM further directed that all tube wells be made operational and that faulty ones be repaired within 24 hours. Additionally, he called for expeditious construction of new tube wells and sewage treatment plants (STP) to increase water availability. Officials were also directed to submit a plan within a week to treat the ammonia present in water that comes from Haryana to Delhi. The Chief Secretary has also been directed to coordinate with the DDA to settle any land related issues in this project.

Yamuna riverfront to be developed on lines of Sabarmati in 5 years: LG

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Delhi Lieutenant Governor VK Saxena on Wednesday said the Yamuna riverfront at Millennium Depot will be developed on the lines of the Sabarmati Riverfront in Ahmedabad within a span of four to five years.

"There are plans to develop a riverfront in Delhi. But it will take time, say another four to five years. We have identified a site near Millennium Depot which will be developed as per norms," Saxena said.

Talking about the project, he said the Delhi Development Authority (DDA) will draw up plans and maps for the riverfront development. The plan is at an initial stage at the moment.

"The length of the stretch will be finalised once the plans are drawn. The DDA, being the land owning agency, will take up the project," he added.

An official, requesting anonymity, said that they have started drawing a concept plan and landscape plan on the riverfront project.

"It will be a massive project and is currently at a nascent stage. We have got the Millennium Depot land and have started drawing up the plan. Development like this takes time and a lot of analysis," he said.

Explaining the roadmap for the project, he said that scientific consultations will be held to ascertain the kind of grass and plants that can be planted there.

THE HINDU
City

Clear floodplains in three days, HC tells slum dwellers

Mehul Malpani
NEW DELHI

The Delhi High Court on Wednesday directed slum dwellers on the Yamuna floodplains here to vacate their jhuggis within three days, failing which they will have to pay ₹50,000 each to the Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) and the Delhi Development Authority (DDA) shall proceed with the demolition.

The court passed the order after being informed that a committee, headed by Lieutenant-Governor V.K. Saxena, has issued directions to clean the Yamuna in view of the January 9 directions of the National Green Tribunal (NGT) which took note of the pollution level.

Advocate Prabhsahay Kaur, appearing for the DDA, submitted that the residents had returned to the same place twice after the encroachments were removed.

Developing riverfront

Meanwhile, the Yamuna riverfront will be developed by the DDA at Millennium Depot, a bus depot near Nizamuddin, the L-G said on Wednesday.

Speaking at Asita East, an ecological site and a spot for bird watching developed by the DDA on the Yamuna floodplains, Mr. Saxena said that the riverfront will be made on the lines of Ahmedabad's Sabarmati riverfront and that the planning is currently in the initial stage.

We plan to turn Asita East, which will host G-20 events, into a prominent tourist destination: L-G

"The DDA is currently drawing up plans. When the plans are ready, we will be able to set a target for the project. But it is expected to take over four-five years," the L-G said.

Talking about Asita East, the L-G said that more G-20 events will be hosted here. A G-20 event and a fashion show is scheduled at another nature site at Baansera Yamuna floodplains this month, he said.

He added that plans are being discussed to allow various events at the ecological site.

"But we will have to avoid loud music events so that we don't disturb the birds that come here," he said.

As per the DDA, at least 63 species of birds have been spotted at Asita East.

"We plan to turn it into a prominent destination for the residents and tourists," he said, adding that some food kiosks will also be permitted.

Mr. Saxena said entry will be ticketed to handle the crowd and for maintenance of the area.

(With PTI inputs)

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
NEW DELHI | THURSDAY | MARCH 16, 2023

DATED

Vacate Yamuna floodplains within 3 days or pay ₹50K, face razing: HC to jhuggis

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Delhi High Court on Wednesday directed slum dwellers on the Yamuna floodplains here to vacate their jhuggis within three days failing which they will have to pay ₹50,000 each to the DUSIB and the Delhi Development Authority (DDA) shall proceed with the demolition.

The court passed the order after being informed that a committee headed by the Lieutenant Governor has issued directions to clean the Yamuna in view of the January 9 directions of the National Green Tribunal (NGT) which took note of the pollution level.

"Strict action may be permitted to be taken by police...the Deputy Commissioner of Police (DCP) concerned of the area will render all support during the said action," the court said dismissing a plea by the residents.

The Delhi Development Authority (DDA), which has been tasked with the demolition of jhuggis, told Justice Prathiba M Singh that the NGT had revived the matter pertaining to pollution of the Yamuna, pursuant to which a high-level committee on January 27 passed directions to take immediate steps to control pollution of the river and remove encroachments there.

Advocate Prabhsahay Kaur, appearing for the DDA, submitted that the residents had come back to the same place twice after the removal of encroachments. Taking note of the submission of the counsel for DDA, the judge asked the counsel representing the residents, "You are occupying river Yamuna. Do you know how much damage is being caused to it?"

The court was hearing a plea by residents of Moolchand Basti located on the Yamuna floodplains at Bela Estate, Rajghat, claiming the DDA and Delhi Police officials visited them in August 2022 and threatened them to vacate their jhuggis which will otherwise be demolished.

Continued on Page 2

Vacate Yamuna floodplains within 3 days or pay ₹50K, face razing: HC to jhuggis

From Page 1

The DDA's counsel told the court the residents had also filed a contempt petition but no contempt case had been made out against the authorities.

She submitted that the Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) said in an affidavit that the residents were not entitled to rehabilitation as their "basti" did not figure in its notified list.

The court directed the DDA to proceed with the demolition after three days and said that no further indulgence will be shown to the petitioners or their families. It also disposed of the contempt plea observing that no contempt was made out and said "You cannot use contempt proceedings to threaten officials".

The court said the residents had concealed certain material facts, as recorded in its order of August 17, 2022, regarding earlier litigations challenging eviction by their fathers and grandfathers which had attained finality till the Supreme Court. When the matter was listed on January 13, the court stayed the proposed demolition considering the harsh winter.

अमर उजाला

दिल्ली की जीवनरेखा के तौर पर विकसित होगा असिता पूर्व

उपराज्यपाल ने डीडीए उपाध्यक्ष संग किया निरीक्षण

अमर उजाला ब्यूरो

चिड़ियों की चहचहाट के बीच लोग कर सकेंगे सैर

नई दिल्ली। पर्यावरण के लिहाज से दिल्ली की जीवनरेखा के तौर पर असिता पूर्व को विकसित किया जा रहा है। बुधवार को एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष के साथ आईटीओ के नजदीक विकसित असिता पूर्व का निरीक्षण किया। पर्यावरण के लिहाज से प्राकृतिक खूबसूरती के बीच चिड़ियों की चहचहाट के बीच लोग सैर का अलग अहसास होगा। चिड़ियों का बसेरा होने की वजह से यहां चुनिंदा गतिविधियों की ही इजाजत होगी। आगंतुकों को यहां प्रवेश करने के लिए टिकट खरीदना होगा।

जी-20 के लिहाज से असिता पूर्व को तैयार किया गया है। करीब 1.2 वर्ग किलोमीटर के दायरे में विकसित हरित क्षेत्र, यमुना के साथ वाटर बॉडी के साथ यहां पहुंचने वालों के लिए फूड कियॉस्क भी लगाए जाएंगे। कार्यों की प्रगति और निगरानी के लिए मंगलवार को उच्च स्तरीय समिति के साथ एलजी ने बैठक की थी। असिता यमुना का दूसरा नाम है। उन्होंने पार्क में हो रही तैयारियों की सराहना की और कहा कि यह तैयारी विदेशी मेहमानों पर भारत की छाप छोड़ेगी। इस मौके पर डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाषीश पांडा ने बताया कि यह क्षेत्र दिल्लीवासियों के लिए प्रकृति का उपहार है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NEW DELHI | THURSDAY, 16 MARCH, 2023 ----DATED----

'DELHI TO GET UNINTERRUPTED WATER SUPPLY DURING SUMMER'

Present Chandrawal WTP plan in 24 hours, CM tells water dept officials

ARGHYA BHASKAR

NEW DELHI: Chief Minister Arvind Kejriwal on Wednesday visited the Chandrawal water treatment plant (WTP) that is currently being upgraded and instructed the officials to rework the schedules within 24 hours and submit a plan to complete the unit by December 2023.

During the review, the CM found out that the progress of the project was not in line with the stipulated time frame and expressed strong displeasure over this. Water minister Saurabh Bhardawaj, DJB Vice Chairman Somnath Bharti and senior officials of Delhi Jal Board were also present on the occasion along with the CM.

The CM instructed the concerned officials to immediately scale up manpower and machinery on the site and leave no scope for any laxity. "I am an engineer myself. I understand how project sites function. We will not tolerate any sort of shortcomings from the contractor's end. There is no room for any delays at this stage," the CM said.

The CM also directed the officials to include provisions for treatment of ammonia at the plant, expressing his dissatisfaction with the present system. He tasked the officials to coordinate with the government's experts to establish a system that can meet with the expected standards.

As per officials, the Delhi government is working to provide adequate water to every household in Delhi. Many projects are going on in Delhi to increase the availability of water and to provide clean water to every household.

The Chief Minister is personally monitoring these projects and reviewing their progress from time to time. In this perspective, many water treatment plants are also being upgraded so that their capacity to treat water can be increased. As per the government statement, the Chandrawal treatment plant is also being upgraded under the plan. After the completion of the project, the capacity of this water treatment plant will be 105 MGD.

'Make all tube-wells operational & repair faulty ones within 24 hours'

ARGHYA BHASKAR

NEW DELHI: Chief Minister Arvind Kejriwal chaired a high-level meeting on Wednesday along with Water minister Saurabh Bharadwaj, Forest minister Gopal Rai, and high-ranking officials of the government to ensure ample water supply for all households in the national Capital.

During the meeting, the CM instructed officials to recharge ground water, increase water availability through tube wells, bring uniformity in the quality of water extracted from lakes, and treat the ammonia present in water coming from Haryana.

The CM emphasised the importance of timely utilisation of available water and preventing its wastage. The CM further directed that all tube wells be made operational and that faulty ones be repaired within 24 hours. Additionally, he called for expeditious construction of new tube wells and sewage treatment plants (STP) to increase water availability.

Officials were also directed to submit a plan within a week to treat the ammonia present in water that comes from Haryana to Delhi. The Chief Secretary has also been directed to coordinate with the DDA to settle any land related issues in this project.

During the review meeting, Kejriwal underlined the importance of increasing the availability of drinking water in the state.

He observed that more water is wasted due to supply chain disruptions than the lack of water itself and pointed out the importance of fixing the supply chain to minimise water wastage. The CM instructed the department to ensure that tube wells are installed within six months of obtaining land. The CM stressed that all tube wells should be in working condition and that all available water should be supplied to the consumers. The CM also emphasised that every tube well should be monitored to ensure that it is running smoothly. He directed the officials to deploy an agency tasked with maintaining tube wells for five years and repairing any breakdowns within 24 hours. The CM made it clear that no tube well should be unutilised and instructed officials to hold engineers accountable if a tube well remains faulty for more than four days. The water extracted from tube wells will be transported to the UGRs from where it would be supplied further.

Furthermore, he directed officials to complete the installation of water flow meters on underground reservoirs to curb wastage of water. Flow meters will also be installed on all the tappings to accurately measure the amount of water being used as per plan. The installation of RO systems and flow meters would also help identify which tube wells are functional and which ones are not.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
THURSDAY, 16 MARCH, 2023 | NEW DELHI ------DATED------

Yamuna riverfront at Millennium Depot will be developed on lines of Sabarmati Riverfront: L-G

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Delhi Lieutenant Governor V K Saxena on Wednesday said the Yamuna riverfront at Millennium Depot here will be developed on the lines of the Sabarmati Riverfront in Ahmedabad within a span of four to five years.

"There are plans to develop a riverfront in Delhi. But it will take time, say another four to five years. We have identified a site near Millennium Depot which will be developed as per norms," Saxena said.

Talking about the project, he said the Delhi Development Authority (DDA) will draw up plans and maps for the riverfront development. The plan is at an initial stage at the moment.

"The length of the stretch will be finalised once the plans are drawn. The DDA, being the land owning agency, will take up the project," he added.

PIC/NAVEEN SHARMA

An official, requesting anonymity, said that they have started drawing a concept plan and landscape plan on the riverfront project.

"It will be a massive project and is currently at a nascent stage. We have got the Millennium Depot land and have started drawing up the plan. Development like this takes time and a lot of analysis," he said.

Explaining the roadmap for the project, he said that scientific consultations will be held to ascertain the kind of grass and plants that can be planted there.

"There are NGT orders too that there cannot be a constructed riverfront in Delhi. So we will have to hold scientific consultations with experts on how to redevelop the area ecologically. There is a bund near the Millennium Depot, so that is a hurdle. We will have to work around it and see if we can remove that barrier. The river swells in monsoons so we have to address that issue as well," he said.

Vacate Yamuna floodplains in three days: HC

NEW DELHI: The Delhi High Court Wednesday directed slum dwellers on the Yamuna floodplains here to vacate their jhuggis within three days failing which they will have to pay Rs 50,000 each to the DUSIB and the DDA shall proceed with the demolition. The court passed the order after being informed that a committee headed by the lieutenant governor has issued directions to clean river Yamuna in view of the January 9 directions of the National Green Tribunal (NGT) which took note of the pollution level.

"Strict action may be permitted to be taken by police the DCP concerned of the area will render all support during the said action," the court said dismissing a plea by the residents.

The DDA, which has been tasked with the demolition of jhuggis, told Justice Prathiba M Singh that the NGT had revived the matter pertaining to pollution of the Yamuna, pursuant to which a high-level committee on January 27 passed directions to take immediate steps to control pollution of the river and remove encroachments there. MPOST

LOUD MUSIC WILL NOT BE ALLOWED: L-G

Guidelines being framed to allow events at Asita East and Baansera

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: To draw visitors to the Asita East and the Baansera ecological sites in the Yamuna riverfront area, Delhi Lt Governor V K Saxena on Wednesday said guidelines are being framed to allow events and programmes there.

However, while framing the guidelines, it has to be "kept in mind that there are no loud musical programmes" at the nature sites, Saxena said.

There is also a proposal to hold some G20 events at these redeveloped floodplains, said the Lt Governor (L-G), who, earlier this month, hosted diplomats from G20 nations and other countries at Asita East. Later this month, another G20 event — a fashion show — has been planned at Baansera.

Saxena said that ticketed entry will be implemented for entry to the two sites. Currently, "visitors can walk in and see the beautiful view but we are planning to have ticketed entries so that people respect the space", he told reporters at an interaction at Asita East . On the guidelines for events, Saxena said, "The DDA (Delhi Development Authority) will be framing guidelines to allow programmes but it has to be kept in mind that there are no loud musical programmes otherwise the birds will leave this place." More than 63 bird species have been spotted at Asita East, according to officials, who added that Rs 50 has been proposed as ticket price for entry to the ecological sites. "People have started coming to Asita East for morning walks and evening walks and it can be a good recreational spot for people of East Delhi, which has the least green cover in the city," an official said.

> **Later this month, another G20 event — a fashion show — has been planned at Baansera**

"Till now, people only had two options — Sanjay Lake and Smriti Van — but this can now be a good option for them. At the moment, the entry is free but we want to ensure that its beauty remains and a ticket system will help," the official said and added that a restaurant will be set up at Asita East. There are security points to thwart untoward incidents and tickets will ensure that "nuisance makers do not gain access", the official said and added that Asita East is a great spot for birdwatchers.

The Asita East project is spread over 197 hectares of land, out of which 90 hectares is with the DDA and the remaining falls under the jurisdiction of Uttar Pradesh's irrigation department. The DDA has developed 90 acres and in accordance with court directions will also be developing the remaining portion under Uttar Pradesh's jurisdiction. The project aims at "restoring ecological character of the flood plains and provide breathable public green space".

Baansera is Delhi's first bamboo theme park aiming at enhancing the ecological character of Yamuna floodplains.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी ▶ 16 मार्च, 2023 ▶ गुरुवार

---DATED---

दिल्ली के हर घर को मिलेगा भरपूर पानीः केजरीवाल

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली में हर घर को साफ और भरपूर पानी उपलब्ध कराने के काम पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। पूरे प्लान की डिटेल मॉनिटरिंग सीएम अरविंद केजरीवाल खुद कर रहे हैं। उनकी नजर गर्मियों के दिनों में दिल्ली में पानी की उपलब्धता में कोई कमी न आने देने पर भी है। इसी के तहत सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कैंप कार्यालय पर जल मंत्री सौरभ भारद्वाज, वन मंत्री गोपाल राय, मुख्य सचिव, डीसीब के सीईओ और संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की।

जिसमें उन्होंने दिल्ली में पानी की उपलब्धता बढ़ाने, उपलब्ध पानी का संपूर्ण इस्तेमाल करने पर विशेष बल दिया। साथ ही, इस दिशा में चल रहे दिल्ली जल बोर्ड के कामों को निर्धारित समय से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा से आने वाले पानी में उपलब्ध अमोनिया को ट्रीट करने का एक सप्ताह में प्लान मांगा है। साथ ही, मुख्य सचिव को जमीन संबंधित समस्या के निपटारे के लिए डीडीए के साथ सामंजस्य स्थापित करने का निर्देश दिया

है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के साथ अगली बैठक 25 मार्च को की जाएगी। जिसमें अब तक हुई बैठकों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की जाएगी।

इलाकों का जलस्तर चिन्हित कर निकाला जाएगा ग्राउंड वाटरः भारद्वाज

जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस समय यमुना में हरियाणा से जो पानी आ रहा है,

उसमें से ज्यादातर हिस्सा इंडस्ट्रियल वेस्ट का है। यमुना में बिना ट्रीट किया हुआ पानी सीधे छोड़ा जा रहा है। इस पानी में अमोनिया की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसे दिल्ली के ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने बैठक में कुछ ऐसे कदम उठाने को कहा कि इतनी मात्रा में आने वाले अमोनियो को भी ट्रीट करने के इंतजाम किए जा सकें। इस दिशा में जल्द से जल्द काम किया जाएगा और करीब 6 महीने के अंदर दिल्ली में ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट यमुना में उपलब्ध कराए जाएंगे जो बड़ी मात्रा में अमोनिया को ट्रीट कर सकें। दिल्ली में जिन इलाकों का जल स्तर ऊपर है, उन इलाकों को चिन्हित किया जाएगा और वहां से ग्राउंड वाटर निकाला जाएगा। इस पानी को ट्रीट कर लोगों के घरों तक सप्लाई की जाएगी।

खराब ट्यूबवेल 24 घंटे के अंदर ठीक कराए जाएंः केजरीवाल

केजरीवाल ने कहा कि हर ट्यूबवेल पर नजर रखी जाए कि वो चल रहा है या खराब है। अगर कोई ट्यूबवेल खराब होता है, तो उसे 24 घंटे के अंदर हर हाल में ठीक किया जाए। किसी एजेंसी को ट्यूबवेल के मेंटेनेंस का काम 5 साल के लिए दिया जाए ताकि अगर ट्यूबवेल का मोटर खराब होता है, तो वो तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर ठीक करे। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि एक भी ट्यूबवेल बंद नही होने चाहिए। इसके लिए इंजीनियर की जिम्मेदारी तय की जाए। अगर कोई खराब ट्यूबवेल चार दिनों तक ठीक नही होता है तो संबंधित इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

सभी ट्यूबवेल चालू हालत में होने चाहिए, दिया निर्देश

समीक्षा बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जमीन मिलने के छह महीने के अंदर ट्यूबवेल लगा दिए जाएं। जितने भी ट्यूबवेल लग गए हैं, वहा यूजीआर पर वाटर फ्लो मीटर लगाने का काम जल्द पूरा किया जाए ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके। फ्लो मीटर सभी टैपिंग पर लगाया जाए जिससे कि जितना पानी निकले, वो पता चल सके। साथ ही, आरओ और फ्लो मीटर लगने से कौन सा ट्यूबवेल चल रहा है और कौन सा बंद है, यह भी पता चल सकेगा। सीएम ने निर्देश दिया कि सभी ट्यूबवेल चालू हालत में होने चाहिए और उससे जितना पानी मिल रहा है, वो सारा पानी आपूर्ति की जाए।

केजरीवाल 25 मार्च को फिर करेंगे समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री ने बनाया विस्तृत प्लान, नहीं होगी गर्मियों में पानी की किल्लत

पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नए एसटीपी का काम तेजी से करें पूराः केजरीवाल

ट्यूबवेल का पानी भी सप्लाई में इस्तेमाल किया जाएः सीएम

केजरीवाल ने हर घर तक पानी की आपूर्ति को लेकर कहा कि ट्यूबवेल और ग्राउड वाटर के सारे पानी की यूजीआर के जरिए सप्लाई की जाए। मतलब ट्यूबवेल का पानी भी सप्लाई में इस्तेमाल किया जाए। अधिकारियों ने बताया कि आरओ प्लांट का डिजाइन तैयार हो गया है। इस पर सीएम ने कहा कि मैं आरओ प्लांट का डिजाइन जाकर देखूंगा। डिजाइन फाइनल होने के बाद जल्द से जल्द इसे चालू किया जाए।

मांग बढ़ने पर बढ़ाए जाएंगे टैंकर

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गर्मी में पानी की मांग बढ़ेगी। ऐसे में पानी आपूर्ति बढाई जाए। साथ ही टैंकर को भी तैयार रखा जाए। दिल्ली में अभी 1200 वाटर टैंकर है। इसकी संख्या को और बढाई जाए, ताकि पानी आपूर्ति में किसी तरह की दिक्कत न आए। अधिकारियों ने दिल्ली जल बोर्ड के 100 वाटर टैंकर के लिए चालकों की कमी बताई। इस पर सीएम ने कहा कि चालकों को जल्द से जल्द हायर कर लिया जाए ताकि कोई भी टैंकर खड़ा न रहे। उन्होंने वाटर टैंकरों की मॉनिटरिंग पर बल देते हुए कहा कि सभी टैंकरों पर जीपीएस लगाया जाए। जिससे कि हर टैंकर को ट्रैक किया जा सके।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE INDIAN EXPRESS, THURSDAY, MARCH 16, 2023

At the Asita East redeveloped ghat on the floodplains. *Mallica Joshi*

The demolition took place close to the Yamuna near Kashmere Gate ISBT. *Express*

Two tales from the Yamuna floodplains

Asita Ghat is redeveloped, plan for a Sabarmati-like riverfront

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, MARCH 15

DELHI'S OWN waterfront – expected to be along the lines of the Sabarmati riverfront – is expected to come up at the site of the controversial Millennium Bus Depot.

Delhi Lieutenant Governor V K Saxena said Wednesday at the Asita East redeveloped ghat that there are plans to create a waterfront at the now-defunct depot "without disturbing the river and the floodplain much".

The Millennium Bus Depot came up before the 2010 Commonwealth Games, but was closed down later since it was built on the Yamuna floodplains and its construction was against the norms, which state that no concrete or permanent structures can come up on the fragile area. The structures that were built, however, still stand.

Saxena said that all norms would be followed in developing the waterfront. The project will be helmed by the Delhi Development Authority (DDA), of which the L-G is the chairperson. According to DDA officials, since concrete structures already exist at the depot, no other construction that violates norms will be done.

Saxena, meanwhile, said the development of the waterfront will take a few years and the project was at the stage of designing. "Once the design is ready, it should be a matter of 2-3 years," he said.

Over the past two years, DDA has been working on the development of the riverfront, and has undertaken 10 projects, of which work is underway at eight. Recently, a delegation of envoys/diplomats of G20 nations visited the redeveloped Asita East ghat, where they also cycled through the curated path.

L-G V K Saxena said redeveloped ghats will serve as places for public gatherings. *Mallica Joshi*

While a part of the redeveloped ghat consists of manicured lawns, a walkway made of interlocking tiles, a cycle track, a parking area, a congregation spot and a selfie spot; the 90-hectare area also has catchment zones, riverine grasslands and ecology, which as per DDA officials, has been home to migratory birds.

It has a restored wetland of about 2.5 hectares and a plantation of 4,000 native trees of the floodplain ecosystem and about 3.35 million riverine grasses.

According to DDA officials, work at the other seven parks is also in full swing.

"While a small part of the Asita East comprises manicured gardens, that is not the objective. We are not making gardens. Development of the ghats is on ecological bases. A part of Asita West is also partly manicured. But by and large, we are developing planted developments, where grasses and trees and shrubs are carefully selected and are native to the area and the riverine ecology," the official said.

Officials also said they had made a conscious decision to not go forth with manicured developments in upcoming projects.

"It has been a learning process. We have made mistakes and corrected them. We know that manicured gardens are not ideal for the riverine ecology," he said.

DDA officials believe that with the new development, the participation of the people of Delhi will increase and encroachments can be controlled as people will be shareholders in the upkeep of the developments.

The L-G, meanwhile, said the redeveloped ghats will serve as places for public gatherings.

Eight shelters are demolished, leaving many without a roof

ABHINAYA HARIGOVIND
NEW DELHI, MARCH 15

THE DEMOLITION of eight shelters located close to the Yamuna near the Kashmere Gate ISBT, has once again put those who are homeless out on the streets, or in this case out on the floodplain.

Five days after the demolition, Pappu Rajbhar, 42, sits on a wall that lies near what used to be a shelter where he would spend the nights. The rubble from the portacabins that were demolished on March 10 is still scattered along the stretch parallel to the Yamuna, between Nigambodh Ghat and Qudsia Ghat.

"They came at night and broke down eight shelters here. There were bulldozers and police. People were sleeping... they came and asked us to leave. Some people were taken away from here, supposedly to another shelter. The rest of us are still here. Some sleep close to the river, and some in a park nearby," said Rajbhar, who is from Ghazipur in Uttar Pradesh and works as a cook at weddings.

Others, like Mohammad Ali, 25, who is from Rampur in Uttar Pradesh, and Pankaj, 26, from Gorakhpur, moved to another shelter near Nigambodh Ghat when theirs was demolished last week. "*Bhaga diya gaya tha* (they ran us off)," said Ali, who works at weddings. Pankaj, who also helps at weddings and had been living in the now demolished shelter for six-seven year said, "Nobody knew this was going to happen. The caretaker suddenly asked us to empty the shelter. Contractors usually come here to hire us, so it's important for us to stay somewhere close by."

The Yamuna Pushta shelters, set up by the Delhi Urban Shelter Improvement Board and managed by NGOs, have been around for a few years now. Aqeel said he had been living in one or the other of the shelters for around eight years. The portacabins that are still standing near Nigambodh Ghat were set up in 2013-14, said Vicky Chandel, the coordinator at the shelter.

A few jhuggis lying along the floodplain were also demolished last week. With her jhuggi demolished, Seema Malik, 40, who said she has been living in the area for nearly 20 years, has been sleeping in the open on the floodplains, with her six-year-old daughter, and her husband, who works at weddings.

At nearby Qudsia Ghat, work is underway on a project to revamp the ghat. The Delhi Development Authority is working to "restore and rejuvenate" the Yamuna floodplains, which includes setting up parks and walkways.

Sunil Kumar Aledia at the Centre for Holistic Development, an organisation that works with homeless people, believes that the demolition drive is on account of the G20 Summit.

Among those using the shelters and people managing ones still standing, there's fear these will also be demolished eventually. "We're hearing that even the shelter near Nigambodh Ghat will be demolished," said Rajbhar.

There is a similar fear at a 'recovery shelter' managed by the Centre for Equity Studies at Geeta Ghat. The shelter, also in portacabins, is meant to provide nursing care and support for homeless people who are injured or unwell, or are dealing with infections like tuberculosis. Ramzan, a medical social worker, who has been working at the shelter from 2016 onwards, said there are 16 shelters along the stretch, of which 8 have been demolished so far. "We don't have any notices so far. But when they took down the other shelters, it just began late in the evening and went on till night," he said.

According to DUSIB data, some of the Yamuna Pushta shelters have capacity of 50 each, while others have a capacity of over 200.

Asked about the removal of occupants from the Yamuna floodplains, L-G V K Saxena said that encroachment on the eco-sensitive zone cannot be condoned. "There are orders making this very clear. The people who are living on the floodplains are being removed and rehabilitated by DUSIB. There are NGT and Supreme Court orders in place that make it clear that encroachments along the floodplains have to be removed. The sum of these encroachments is that the pollution levels in the river go up... DUSIB has good infrastructure and enough capacity to house the people have have been removed. Many of them are poor people and need to solve supported, but not at the cost of the environment," he said.

Vacate within three days, Bela Estate occupants told by HC

MALAVIKA PRASAD
NEW DELHI, MARCH 15

THE DELHI High Court Wednesday directed the residents to vacate jhuggis on the Yamuna floodplains within three days, after it was informed that directions had been issued by a committee chaired by Lieutenant Governor V K Saxena to clean the river in view of directions from the National Green Tribunal (NGT).

A single-judge bench of Justice Prathiba Singh pulled up the residents after it was informed by the Delhi Development Authority (DDA), the agency tasked with the demolition of the jhuggis, that the NGT had revived the matter pertaining to pollution of the Yamuna, pursuant to which a high-level committee meeting directed DDA on January 20 to submit action plan on removal of encroachments in the floodplain. The court was told that the committee was constituted under chairmanship of the L-G after NGT took note of the pollution in January.

Advocate Prabhsahay Kaur, appearing for the DDA, submitted that the residents had come back to the same place twice after the removal of encroachments. Justice Singh then told the counsel appearing for the residents, "You are occupying Yamuna river. Do you know how much damage is being caused to it?" The counsel for petitioners prayed that they may be rehabilitated submitting that they will vacate, seeking a week's time for the same.

The court was hearing a plea moved by residents of Moolchand Basti located on Yamuna floodplains at Bela Estate, Rajghat, claiming that DDA and police visited them in August 2022 and "threatened to vacate their jhuggis, otherwise the same will be demolished forcefully".

Kaur submitted that residents had moved a contempt plea as well and that no contempt had been made out against authorities. She submitted that the Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) said in an affidavit that residents were not entitled to rehabilitation as their bastis did not feature on its notified list.

The court directed residents to vacate the premises within three days, failing which they would have to pay Rs 50,000 each to the DUSIB. The court said the residents had concealed certain material facts, as recorded in its order of August 17, 2022, including that the fathers of the 18 petitioners had instituted litigation in respect of the same property right up to the Supreme Court and lost. The HC in November 2022, directed that bailable warrants be issued against all petitioners and ordered them to appear before it. The petitioners had also filed a contempt case seeking identical reliefs.

On January 13, the court considered "harsh winter" and stayed the demolition of jhuggis at the time. It directed DDA on Wednesday to proceed with demolition and said no further indulgence would be granted to petitioners or their families. The court also disposed of the contempt plea observing that no contempt was made out.

SEEN AT JANTAR MANTAR

At an event in the capital to check the stray dog 'menace', Wednesday. *Jignasa Sinha*

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ E TIMES OF INDIA, NEW DELHI -------DATED------ THURSDAY, MARCH 16, 2023

Cue from Sabarmati: DDA readies plan to develop Yamuna waterfront

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: Lieutenant governor VK Saxena Wednesday said DDA will develop the Yamuna waterfront at old Millennium Depot on the lines of Ahmedabad's Sabarmati Riverfront.

A meeting in this regard has taken place at the ministry level, officials said, adding DDA will appoint a consultant soon.

The project is in nascent stages, the LG said. "It will be implemented without disturbing the floodplain and in accordance with existing norms. After design approval, it won't take more than two years to implement the project," he said.

A senior DDA official said as per NGT's directions, no concrete construction will take place at the Yamuna waterfront. The project, he added, will be in continuation of the development work proposed at New India Garden, which is next to the depot and part of Central Vista.

"We had submitted a presentation before officials of the housing and urban affairs ministry. There is already a bund at the site, so no new construction will be required," the official said, adding that the department has already started planting riverine grass near the proposed site as part of the 'green development project'.

File photo

REVAMPED: Asita East has turned over a new leaf

The project to restore the riverfront was conceived following a 2015 NGT order. The work on the riverfront, DDA officials said, started in 2017 and was monitored by the NGT-appointed Yamuna Monitoring Committee, set up in 2018.

During restoration work, the authority removed some DUSIB shelters and encroachment as part of the drive to keep the riverfront clean.

"These are zero-tolerance areas and as per the apex court's directions, no one can live here. The people living in shelter homes have been carefully rehabilitated to other DUSIB shelters," said the LG.

The LG said various measures are being taken to improve the water quality on the 22km Yamuna bank from Okhla barrage to Wazirabad barrage. The biochemical oxygen demand and chemical oxygen demand will be improved by June 30, he added.

Saxena also said the two riverfronts of Baansera and Asita East have already been thrown open to the public. In addition to pathways and green lawns, 15,000 bamboo saplings have been planted at the sites. DDA is planning to host a series of events at the riverfront sides for guests participating in the G20 meetings.

"At Baansera, we will organise a fashion show in March-end, which will see participation from representatives of embassies, followed by other events in June and September. At Asita, we will hold events during the same period," he said.

Delhi has few tourist spots and places like Kartvyapath are mostly choked, which could see footfall increasing at the riverfronts once the restoration work is completed. "At a later stage, we will make the entry ticketed and bring facilities like food kiosks," said Saxena.

8 polluting units sealed in W Delhi's industrial area

Times News Network

New Delhi: In a recent report submitted to the National Green Tribunal (NGT), Delhi Pollution Control Committee (DPCC) stated that it has sealed over eight units engaged in grinding, cutting and storing plastic waste in a market in west Delhi's Tikri Kalan industrial area.

DPCC acted following the tribunal's order to check and act against the polluters in the area.

After the closure of the units, several unorganised units managing waste have appeared in the region, the report stated.

DPCC stated that such industries were running in non-confirming areas and suggested that the Delhi Development Authority (DDA) cancel their licences. "It was requested to look into the matter and ensure demarcation of the market through a boundary wall and take action against the units...MCD may take action against any illegal units in residential areas in Tikri and ensure the removal of encroachment as per their bylaws. DDA and MCD may also join the drive with the revenue department and DPCC for taking prompt action for the closure of such units on the spot," DPCC said.

DPCC, along with the revenue department and Delhi Police, inspected the area on December 14 and 22 last year and found several grindings, plastic waste storage, etc. Another joint inspection of the site was carried out on February 16 and no grinding, cutting and other activities were found but scrap management of plastic, rubber, metal, etc, was on at footpaths.

HC directs slum dwellers on floodplain to vacate in 3 days

New Delhi: Delhi High Court on Wednesday directed slum dwellers on the Yamuna floodplain here to vacate their jhuggis within three days, failing which they will have to pay Rs 50,000 each to DUSIB and Delhi Development Authority (DDA) shall proceed with the demolition.

The court passed the order after being informed that a committee headed by the lieutenant governor has issued directions to clean river Yamuna in view of the January 9 directions of the National Green Tribunal (NGT), which took note of the pollution level. "Strict action may be permitted to be taken by police. The DCP concerned of the area will render all support during the said action," the court said dismissing a plea by the residents.

Advocate Prabhsahay Kaur, appearing for the DDA, submitted that the residents had come back to the same place twice after the removal of encroachments. The judge asked the counsel representing the residents, "You are occupying river Yamuna. Do you know how much damage is being caused to it?" PTI

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 16 मार्च 2023

DATED

राजधानी में गर्मी में नहीं होगी पानी की किल्लत : सीएम

गर्मियों में पानी सप्लाई के मुद्दे पर हुई समीक्षा बैठक

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कैंप कार्यालय पर गर्मियों में पानी सप्लाई के मुद्दे पर समीक्षा बैठक की। इसमें जल मंत्री सौरभ भारद्वाज, वन मंत्री गोपाल राय, मुख्य सचिव, डूसिब के सीईओ और संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सीएम ने कहा कि पानी के इस्तेमाल और उसकी बर्बादी रोकने के लिए काम समय पर पूरे किए जाएं। सभी ट्यूबवेल चालू हों और नए ट्यूबवेल लगाने का काम तेजी से हो और खराब ट्यूबवेल 24 घंटे के अंदर ठीक किए जाएं। पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नए एसटीपी का काम जल्द पूरा किया जाए।

24 घंटे में खराब ट्यूबवेलों को ठीक करने के निर्देश

सीएम केजरीवाल ने पानी के सही इस्तेमाल और बर्बादी रोकने के दिए निर्देश

उन्होंने कहा कि जमीन मिलने के छह महीने में ट्यूबवेल लगा दिए जाएं। ट्यूबवेल के यूजीआर पर वॉटर फ्लो लगाने का काम जल्द पूरा किया जाए। फ्लो मीटर सभी टैपिंग पर लगाया जाए, ताकि यह पता चले कि कितना पानी निकला है। किसी एजेंसी को ट्यूबवेल के मेंटिनेंस का काम 5 साल के लिए दिया जाए, ताकि ट्यूबवेल का मोटर खराब होता है, तो वह 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाए। बंद ट्यूबवेल के लिए इंजीनियर की जिम्मेदारी तय होगी। अगर कोई खराब ट्यूबवेल चार दिनों तक ठीक नहीं होता है तो संबंधित इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने एसटीपी के लिए जमीन मिलने में आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा की और इसका जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। जमीन मिलने में सबसे अधिक डीडीए से दिक्कत आ रही है। मुख्यमंत्री ने इस मसले का निपटारा करने की जिम्मेदारी मुख्य सचिव को दी है। अन्य विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित कर जमीन संबंधी समस्या का निस्तारण करने की जिम्मेदारी जल मंत्री सौरभ भारद्वाज को दी गई।

सीएम ने कहा कि झील के लिए एक एसओपी बने। झील में पानी डालने से भूजल स्तर बढ़ता है। झील बनने के कितने दिनों बाद तक उसमें पानी डालेंगे और कितना पानी निकालें, इसके लिए यह एसओपी तैयार होगी। झील के साथ आरओ प्लांट लगाने का काम 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाए। उन्होंने ट्यूबवेल और भूजल की यूजीआर के जरिए सप्लाई करने की बात की। उन्होंने कहा कि वजीराबाद में अमोनिया रिमूवल प्लांट लगाने जा रहे हैं। इसका प्लान एक हफ्ते में तैयार होगा। यहां से वीआईपी एरिया में पानी की आपूर्ति की जाती है। साथ ही एक हफ्ते में वॉटर बॉडीज का दोबारा सर्वे करने के निर्देश भी दिए गए हैं। डीडीए के पास करीब 250 वॉटर बॉडीज है। इसमें सीवर और गंदा पानी जा रहा है। डीडीए से बात कर इसे भी ट्रीट किया जा सकता है।

दिसंबर तक पूरा करें चंद्रावल प्लांट का काम: CM

■ विस, नई दिल्ली: सीएम ने चंद्रावल में 105 एमजीडी के नए बन रहे डब्ल्यूटीपी का दौरा कर उसके काम की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि चंद्रावल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट तय समयसीमा के अनुसार नहीं है। इसे लेकर सीएम ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने काम कर रही एजेंसी को एक दिन में पूरा प्लान सौंपने के निर्देश दिए। इस काम को सीएम ने दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। इससे 22 लाख लोगों को साफ पानी मिलने की उम्मीद है।

105 एमजीडी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट की मुख्यमंत्री ने समीक्षा की

चंद्रावल प्लांट को अपग्रेड किया जा रहा है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इस वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 105 एमजीडी की हो जाएगी। इसे दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस साइट पर तुरंत मैनपावर और मशीनरी बढ़ाएं। किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वह खुद इंजीनियर हैं और समझते हैं कि प्रोजेक्ट स्थल पर काम किस तरह होते हैं।

यमुना के फ्लडप्लेन से 3 दिन में खाली करें झुग्गियां : हाई कोर्ट

■ विस, नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां यमुना की बाढ़ से प्रभावित होने वाले इलाकों में झुग्गियों में रहने वाले लोगों को तीन दिन के अंदर जगह खाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) को 50-50 हजार रुपये का भुगतान करना होगा और डीडीए उनकी झुग्गियों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

हाई कोर्ट को बताया गया था कि एलजी की अध्यक्षता वाली समिति ने एनजीटी के 9 जनवरी के निर्देशों के मद्देनजर यमुना नदी को साफ करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। उन इलाकों में रहने वाले लोगों की याचिका खारिज करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने कहा कि पुलिस को सख्त कार्रवाई की इजाजत दी जा सकती है। संबंधित इलाके के डीसीपी इस कार्रवाई के दौरान हर जरूरी मदद मुहैया कराएंगे। डीडीए ने कोर्ट को बताया कि एनजीटी ने यमुना का पानी प्रदूषित होने से संबंधित मामले पर फिर से गौर किया था, जिसके बाद 27 जनवरी को उच्चस्तरीय समिति ने नदी के प्रदूषण को कंट्रोल करने और वहां से अतिक्रमण हटाने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए थे। डीडीए की ओर से पेश वकील प्रभासहाय कौर ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद झुग्गीवासी दो बार उसी जगह पर वापस आ गए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 16 मार्च, 2023

मिलेनियम डिपो की जमीन पर बनेगा साबरमती जैसा रिवरफ्रंट

आइटीओ यमुना पुल के पास असिता ईस्ट प्रोजक्ट का निरीक्षण करते एलजी● ध्रुव कुमार

- एलजी ने कहा-मानदंडों के अनुसार किया जाएगा विकसित
- किया 'असिता ईस्ट' का दौरा, योजना पर की बात

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने कहा कि चार-पांच वर्ष के भीतर मिलेनियम डिपो की जमीन पर अहमदाबाद के साबरमती जैसा रिवरफ्रंट विकसित किया जाएगा। बुधवार को 'असिता ईस्ट' के दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में एलजी ने कहा कि दिल्ली में एक रिवरफ्रंट विकसित करने की योजना है, लेकिन अभी इसमें समय लगेगा। हालांकि, इसके लिए मिलेनियम डिपो के पास हमने एक साइट की पहचान कर ली है, जिसे मानदंडों के अनुसार विकसित किया जाएगा।

एलजी ने कहा कि डीडीए रिवरफ्रंट के लिए प्लान और मैप तैयार करेगा और काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना तैयार होने के बाद खंड की लंबाई को अंतिम रूप दिया जाएगा। जमीन की मालिक एजेंसी होने के नाते दिल्ली विकास प्राधिकरण इस परियोजना को अपने हाथ में लेगा।

एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने रिवरफ्रंट परियोजना पर एक अवधारणा और लैंडस्केप योजना तैयार करना शुरू भी कर दिया है। यह एक विशाल परियोजना होगी, जो अभी प्रारंभिक दौर में है। इस तरह के विकास में समय लगता है, क्योंकि इसके तहत बहुत सारे विश्लेषण होते हैं। वहां किस तरह की घास और पौधे लगाए जा सकते हैं, इसका पता लगाने के लिए भी वैज्ञानिक परामर्श किया जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश हैं कि दिल्ली में रिवरफ्रंट का निर्माण नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें विशेषज्ञों के साथ परामर्श करना होगा कि इस क्षेत्र को पारिस्थितिकी के हिसाब से कैसे पुनर्विकसित किया जा सकता है। डिपो के पास एक बांध है, जो बड़ी बाधा है। इसपर काम करना होगा और देखना होगा कि हम इस बाधा को कैसे दूर कर सकते हैं। नदी उफनने की समस्या का समाधान भी ढूंढना होगा।

---DATED---

दीवाली पर मिलेगा पेंट हाउस का तोहफा

संजीव गुप्ता● नई दिल्ली

- पहली बार बनाए इतने महंगे फ्लैट, द्वारका सेक्टर 19 में हो रहा निर्माण, तमाम सुविधाएं मिलेंगी
- एक पेंट हाउस की कीमत होगी तीन करोड़ से भी ज्यादा, 2019 से प्रोजेक्ट पर चल रहा है काम

आम आदमी को आशियाना देने वाला दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अब खास लोगों को लग्जरी पेंट हाउस का दीवाली तोहफा देने जा रहा है। तकरीबन चार साल की जद्दोजहद के बाद अंततः द्वारका सेक्टर-19 में पेंट हाउस और सुपर एचआइजी फ्लैटों की स्कीम लांच की जाएगी। 66 वर्षों के इतिहास में डीडीए ने इतने महंगे फ्लैट और आवास पहली बार ही बनाए हैं। हालांकि इस अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर डीडीए 2019 से निरंतर काम कर रहा है। कोरोनाकाल में इनका निर्माण अधूरा रह गया था। अब डीडीए इन्हें जल्द तैयार कराने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि इस साल शारदीय नवरात्र के आसपास डीडीए की ये विशेष आवासीय स्कीम आ जाएगी।

पेंट हाउस और सुपर एचआइजी फ्लैट की आवासीय योजना पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में लांच होगी। पेंट हाउस की कीमत तीन करोड़ के ऊपर हो सकती है। यह फ्लैट ग्रीन बिल्डिंग सिद्धांत पर तैयार किए जा रहे हैं। इनमें सोलर हीटिंग, आर्गेनिक वेस्ट डिस्पोजल और बिजली की कम खपत जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

दिल्ली एयरपोर्ट नजदीक, मिलेगा लाभः द्वारका से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की दूरी ज्यादा नहीं है। ऐसे में डीडीए अधिकारियों को पूरी उम्मीद है कि एयरपोर्ट के पास होने से उन्हें इस योजना के लिए निश्चित तौर पर लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। द्वारका सेक्टर-19 बी में बनाए जा रहे इन फ्लैटों के साथ ही 946 एचआइजी और 728 ईडब्लूएस फ्लैट भी शामिल हैं। कुल 11 रेजिडेंशियल टावर में ये फ्लैट बनाए जा रहे हैं। सात टावरों में पेंट हाउस होंगे व हर टावर में दो-दो पेंट हाउस रहेंगे। पेंट हाउस टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर होंगे।

23000 फ्लैटों की आवासीय स्कीम अप्रैल में

इससे पहले अप्रैल माह में डीडीए करीब 23 हजार फ्लैटों की एक अन्य आवासीय योजना भी लांच करने वाला है। इस योजना के ज्यादातर फ्लैट नरेला में हैं, जो एलआइजी एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी वाले हैं। कुछ फ्लैट एचआइजी श्रेणी के हैं जो वसंत कुंज की प्राइम लोकेशन पर हैं।

❝ पेंट हाउस और सुपर एचआइजी फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं। इन्हें पूरा होने में लगभग छह माह का समय और लग सकता है। इसके बाद ही इनकी स्कीम लांच की जाएगी। अलबत्ता, नई आवासीय योजना इसी अप्रैल महीने में लांच कर दी जाएगी। इसमें शामिल ज्यादातर फ्लैट नरेला में जबकि कुछ वसंत कुंज में भी हैं।

वी एस यादव
आयुक्त (आवास), डीडीए

यमुना डूब क्षेत्र में बनी झुग्गियों को तीन दिन में खाली करें : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: यमुना के डूब क्षेत्र की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट ने तीन दिन के भीतर अपनी झुग्गियां खाली करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने आदेश का अनुपालन नहीं किया तो उन्हें दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) को 50 हजार रुपये का भुगतान करना होगा और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी।

पीठ ने यह निर्देश तब दिया जब अदालत को सूचित किया गया कि एनजीटी के नौ जनवरी के निर्देशों के तहत उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा यमुना नदी को साफ करने का आदेश दिया गया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 16 मार्च 2023

यमुना किनारे साबरमती जैसा रिवरफ्रंट बनाने की तैयारी

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे बनाए गए रिवरफ्रंट की तर्ज पर अब दिल्ली में भी यमुना किनारे एक रिवरफ्रंट डिवेलप करने की तैयारी चल रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को बताया कि इसके लिए जगह भी तय कर ली गई है। एलजी ने बताया कि पूर्वी दिल्ली में रिंग रोड और एनएच-24 की क्रॉसिंग के पास जिस जगह पहले डीटीसी का मिलेनियम बस डिपो बनाया गया था, उसी जगह पर यमुना किनारे इस रिवरफ्रंट को डिवेलप करने की योजना है। हालांकि, इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि अभी यह योजना काफी शुरुआती चरण में है, लेकिन फिर भी तीन-चार साल में इसे डिवेलप किया जा सकता है। इस योजना को अमली जामा पहनाने का जिम्मा डीडीए को सौंपा गया है, जो इसकी प्लानिंग और डिजाइनिंग से लेकर इसके निर्माण पर काम करेगा। मिलेनियम डिपो के पास यमुना पुश्ता का जो इलाका है, वहीं पर यह रिवरफ्रंट बनेगा। मिलेनियम डिपो से यमुना के डूब क्षेत्र की दूरी करीब 200 मीटर है, इसीलिए इस जगह को चुना गया है, क्योंकि मिलेनियम डिपो के लिए जो निर्माण किया गया था, उसका इस्तेमाल करते हुए यहां रिवरफ्रंट डिवेलप करने की ज्यादा अच्छी संभावनाएं दिख रही थीं। यह रिवरफ्रंट कितना लंबा होगा और इसके आसपास किस तरह की सुविधाएं विकसित की जाएंगी, इस बारे में अभी डीडीए कॉन्सेप्ट प्लान और लैंडस्केपिंग प्लान तैयार कर रहा है। जरूरत पड़ने पर कंसल्टेशन के लिए किसी एजेंसी को भी हायर किया जा सकता है।

LG ने बताया कि इसके लिए जगह भी तय कर ली गई है

हिन्दुस्तान
NEW DELHI
THURSDAY
MARCH 16, 2023

यमुना के डूब क्षेत्र से जल्द झुग्गियां हटाने का आदेश

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को यमुना के डूब क्षेत्र में झुग्गियों में रहने लोगों को तीन दिन के भीतर झुग्गियां खाली करने का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर उन्हें डीयूएसआईबी को 50 हजार रुपये का भुगतान करने को कहा गया है। साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण को इन झुग्गियों को हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को कहा है।

बता दें कि उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली एक समिति ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के 9 जनवरी के निर्देशों के मद्देनजर यमुना नदी को साफ करने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने यमुना में प्रदूषण के स्तर पर ध्यान देते यह निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने इन झुग्गियों में रहने वाले निवासियों की एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस को सख्त कार्रवाई करने की अनुमति दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस क्षेत्र के संबंधित पुलिस उपायुक्त उक्त कार्रवाई के दौरान डीडीए को सहयोग करेंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण को झुग्गियों के हटाने का काम सौंपा गया है। डीडीए ने बताया कि एनजीटी ने यमुना के प्रदूषण से संबंधित मामले को फिर से शुरू किया है।

तत्काल कदम उठाएं

पीठ ने कहा कि यमुना नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करने और वहां से अतिक्रमण हटाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। डीडीए की तरफ से पेश अधिवक्ता प्रभासहाय कौर ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद निवासी दो बार उसी स्थान पर वापस आ गए थे। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) को एक हलफनामे में कहा कि निवासी पुनर्वास के हकदार नहीं है।

DATE Hindustan Times

LG: Sabarmati-like makeover plan for Yamuna riverfront

HT Correspondent
htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Delhi lieutenant governor VK Saxena on Wednesday said that a waterfront on the lines of Sabarmati Riverfront in Ahmedabad was being planned along the river Yamuna at the site of the erstwhile Millennium bus depot.

He added that the details of the plan are being worked out and the Delhi Development Authority (DDA) -- the nodal agency for the Yamuna Riverfront rejuvenation project -- will soon appoint a consultant for the proposed project. Saxena is the chairperson of DDA.

"A Sabarmati Riverfront-like waterfront will be developed along the Yamuna. It will come up where the Millennium bus depot was located. The project is in the nascent stage. Its design and other details are being worked out. The DDA will then appoint a consultant for the project," Saxena said

Referring to the work done by DDA in developing Asita East, where the LG hosted G20 diplomats on March 5, Saxena said that the city needs more such open and green eco-friendly recreational spaces which are easily accessible to the public. The Asita East project involved restoring the Yamuna floodplains in an area of 197 hectares, 90 hectares of which belongs to DDA and is situated along the Vikas Marg in east Delhi. The remaining land is owned by Uttar Pradesh irrigation department.

According to senior DDA officials, the plan is to develop the site as a green area. "There will be no concrete construction in accordance with the National Green Tribunal's directions. This will be in continuation to the development work proposed at the New India Garden, site for which is located near the depot. There is already a bund constructed at the site, so no new construction will be required. A presentation in this regard was made before Union ministry of housing and urban affairs," an official said. Manoj Misra, convener of the Yamuna Jiye Abhiyan, said that the site where the Millennium depot was constructed is part of the floodplain. "The NGT has already said that it is floodplain. The paving on that stretch and the constructions should have been removed. It will be illegal and immoral. The floodplain must be restored to its natural state," he added.

LG SAXENA SAID THAT THE CITY NEEDS MORE SUCH OPEN AND GREEN ECO-FRIENDLY RECREATIONAL SPACES WHICH ARE EASILY ACCESSIBLE TO THE PUBLIC